Result Mitra IAS/PCS Daily Magazine Content

संप्रभु ग्रीन बॉन्ड (SGRB)

➢ चर्चा में क्यों ?

- कई वैश्विक उभरते बाजारों की तरह भारत ने भी कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए निधि (Fund) देने के क्रम में "संप्रभु ग्रीन बॉन्ड" (SGRBs, Sovereign Green Bond) की ओर रुख किया लेकिन इसके लिए निवेशक की मांग कमजोर बनी हुई है।
- संप्रभु ग्रीन बॉन्ड (SGRBs) सरकारों को स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी जुटाने में मदद करते हैं।
- भारत में SGRBs के कम उधार लेने की लागत को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है नतीजतन ग्रिड–स्केल सौर परियोजना सहित कई प्रमुख परियोजनाओं के लिए नियोजित आवंटन कम हो गई है।
- मौन निवेशक ब्याज के साथ SGRBs के फंडिंग अंतराल को पाटने के लिए सामान्य राजस्व पर भरोसा कर रहा है।
- हालांकि संप्रभु ग्रीन बॉन्ड देश की कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए तरलता के मुद्दों को संबोधित करना, पारदर्शिता की रिपोर्टिंग में सुधार करना, देश की स्थिरता बॉन्ड को बढ़ावा देने सहित ग्रीन फाइनेंस के विस्तार करने में मदद कर सकता है।

➢ संप्रभु ग्रीन बॉन्ड क्या है ?

- "संप्रभु ग्रीन बॉन्ड" सरकारों, निगमों और बहुपक्षीय बैंकों द्वारा जारी किए गए ऋण उपकरण है जो उत्सर्जन को कम करने या जलवायु लचीलापन बढ़ाने वाली परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का काम करती है।
- संप्रभु ग्रीन बॉन्ड (SGRBs) के जारीकर्ता आमतौर पर पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में कम ब्याज पर इस बॉन्ड की पेशकश करते है तथा निवेशकों को आश्वस्त करते हैं कि इससे प्राप्त आय का उपयोग विशेष रूप से हरे निवेश (Green Investment) के लिए किया जाएगा।
- SGRBs के उपज में अंतर जिसे ग्रीन प्रीमियम या ग्रीनियम के रूप में जाना जाता है ग्रीन बॉन्ड के लागत लाभ को निर्धारित करता है।
- एक उच्च ग्रीनियम SGRBs के जारीकर्ता को कम लागत पर धन जुटाने की अनुमति देता है जिससे ग्रीन इन्वेस्टमेंट और अधिक आकर्षक हो जाता है।
- ग्रीन बॉन्ड के निवेशक अक्सर स्थिर, दीर्घकालिक रिटर्न की तलाश करते हैं तथा ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए अपने फंड के एक हिस्से को आवंटित करने के लिए आंतरिक या बाहरी रूप से निर्भर हो सकते हैं।
- अपनी विशिष्ट क्षमता के बावजूद ग्रीन बॉन्ड ऋण बाजार और समग्र जलवायु वित्तपोषण का एक छोटा सा हिस्सा बनते है इसलिए सरकारें इसके रिपोर्टिंग प्रथाओं को मजबूत करती है और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन पेश करती है।

- वर्ष 2022 में संप्रभु ग्रीन बॉन्ड को भारत सरकार के तहत संप्रभु संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है।
- सरकार द्वारा संप्रभु ग्रीन बॉन्ड जारी करने का यह फ्रेमवर्क "ग्रीन प्रोजेक्ट्स" (हरित परियोजनाओं) को परिभाषित करता है जो संसाधन उपयोग में ऊर्जा दक्षता को परिभाषित करने, कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने में मदद के लिए है।
- वर्ष 2022–23 के बाद से भारत सरकार द्वारा SGRBs को कुल आठ बार जारी किया गया, जिससे लगभग 53,000 करोड़ रुपए जुटाए गए।
- प्रत्येक वर्ष सरकार SGRBs से रेल मंत्रालय के माध्यम से ऊर्जा कुशल तीन चरण इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उत्पादन के लिए लगभग 50% आय का उपयोग करती है।
- वर्ष 2024-25 के लिए SGRBs के तहत पात्र योजनाओं के आवंटन के लिए संशोधित अनुमानों में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण के लिए 8,000 करोड़ रुपए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4607 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 124 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
- इसके अलावा ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

➢ SGRBs के लिए निवेशक उत्साहित क्यों नहीं है ?

- भारत के SGRBs ने मौन निवेशकों की मांग के कारण आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया है जिससे सरकार के लिए ग्रीनियम को सुरक्षित करना मुश्किल हो गया है।
- सरकार द्वारा SGRBs के विदेशी निवेशकों के लिए नियमों में ढील देने सहित कई प्रयासों के बावजूद इसके नीलामी में सीमित भागीदारी देखी गई है।
- वैश्विक स्तर पर ग्रीनियम 7–8 आधार अंकों तक पहुंच गया है जबकि भारत में यह सिर्फ 2–3 आधार अंकों तक ही सीमित है जो एक व्यवहार्य फंडिंग स्रोत के रूप में SGRBs के विस्तार को सीमित करता है।

- भारत में सामाजिक प्रभाव निजी और जिम्मेदार निवेश जनादेश का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव है।
- SGRBs से पर्याप्त आय जुटाने में सरकार की अक्षमता इसके तहत पात्र योजनाओं के लिए धन को प्रभावित करते हैं और इसके कमी को पूरा करने के लिए सामान्य राजस्व पर दबाव डालती है।
- 2024–25 के प्रारंभ के लिए SGRBs आय से अनुमानित धन की आवश्यकता 32,061 करोड़ थी लेकिन निवेशकों के बीच कम उत्साह के कारण SGRBs को बेचने के असफल प्रयासों के कारण इसके संशोधित अनुमान को 25,298 करोड़ रुपए तक कर दिया गया।
- जिसके परिणाम स्वरुप ग्रिड–स्केल सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली एक योजना जिसके लिए शुरुआती आवंटन 13000 करोड़ रुपए था, उसे कम करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया।

➢ आगे का रास्ता :

- हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार उभरते बाजार SGRBs जारीकर्ता, उन्नत बाजार SGRBs जारीकर्ता की तुलना में हरे और सामाजिक परियोजनाओं के संयोजन को और अधिक बॉन्ड जारी करते हैं।
- दूसरे शब्दों में हरे और सामाजिक परियोजनाओं को जोड़ने वाली परियोजनाओं के लिए बॉन्ड जिसे स्थिरता बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है, निवेशक के हितों को बढ़ावा देकर आय बढ़ा सकता है।
- विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि SGRBs ने जारी आवंटन और प्रभाव रिपोर्ट तैयार करने में काफी समय लिया है जो निवेशकों के हित को प्रभावित करता है।
- अधिकांश निवेशकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि SGRBs के आवंटन और प्रभाव रिपोर्ट में प्रदान की गई जानकारी का उपयोग, आय के उपयोग के आकलन के लिए किया जाता है, लेकिन निवेशकों का मानना है कि अगर SGRBs के आय अपने आंतरिक डेटा मॉडल और कार्य प्रणाली को और अधिक परिष्कृत करने के लिए मात्रात्मक डेटा का उपयोग करती है, तो यह और सुलभ हो सकता है।

- निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए भारत बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ अपनी ग्रीन बॉन्ड रणनीति को वापस करने के लिए अपनी क्रेडिट रेटिंग के साथ भी साझेदारी कर सकता है।